(b) if so, the number of applications received in this regard and the names of the candidates called for interview;

(c) the criteria for the selection with regard to experience, qualification and seniority in the relevant field;

(d) the names of the successful candidates and whether any panel was prepared; and

(c) if so, the details thereof, and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): (a) Yes, Sir.

(b) 16 applications were received in this regard. None of the candidates were called for interview.

(c) The suitability of the candidates was assessed based on experience, qualification, seniority amongst the eligible candidates and their Annual Confidential Reports.

(d) and (c) A merit list consisting of three candidates viz. Km. Shobhna Srivastava, Smt. Sharda Vashisth and Shri C.S. Verma, in that order, was prepared.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED AND UNSTARRED QUESTIONS SET FOR THE 16TH APRIL, 1999

Gauge conversion in Tamil Nadu

*361. SHRI S. AGNIRAJ: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) what is the total length of tracks converted into broad guage in Tamil Nadu;

(b) t w much distance of tracks is yet to be converted into broad gauge;

(c) by when this project is likely to be completed;

(d) whether it is a fact that the procjets are running behind their schedules; and

(e) the action taken for timely completion of these projects?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NITISH KUMAR): (a) The total length of track converted into broad gauge in Tamil Nadu till dates is 820 km.

(b) Work is in progress for conversion of 584 km in Tamil Nadu and another 443 km have been included in the budget and will be taken up after the requisite clearances have been obtained. The remaining MG lines have not yet been planned for conversion.

(c) The gauge conversion of Arakkonam-Chengalpet is planned to be completed in 1999-2000. For the other lines no target dated has yet been fixed.

(d) No, Sir.

(e) The projects are being progressed as per priority approved by the Cabinet Committee on Economic Affairs and availability of resources.

Blood Donation by Professional Donors

*362. SHRI ABANI ROY: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that professional blood donors are still donating blood in various Government hospitals in the capital, inspite of orders of the Supreme Court for ban on such donors;

(b) if so, the facts and details thereof;

(c) whether, on many occasions, Government hospitals in the capital have given blood to the needy patients, which was expired one; and

(d) if so, the facts and details thereof and the action contemplated by Government in this regard?

---

*The sitting of the Rajya Sabha on Friday May, 16th April, 1999 was cancelled. Answeres to Questions put down in the lists for the day were laid on the Table of the House on Monday, the 19th April, 1999.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI DALIT EZHILMALAI): (a) According to the Delhi State AIDS Control Society, there is no case of donation of blood by professional donors in various Government hospitals in the capital. This has been confirmed by surveys carried out by Drugs Control Department, Government, of NCT of Delhi from time to time.

(b) Does not arise.

(c) No case of supply of date expired blood has come to the notice of Drugs Control Department of Govt, of NCT of Delhi.

(b) Does not arise.

सरकारी अस्पतालों पर दबाव कम करने के उपाय

*363. **चौधरी हरमोहन सिंह यादव** :

श्री ईश दत्त यादव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी अस्पतालों पर दबाव को कम करने हेतु कुछ उपाए किए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं,

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च की जाएगी,

(घ) क्या सरकारी अस्पतालों को सुदृढ़ बनाने और उनके कार्यकरण में सुधार लाने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं, और

(ड़) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ड़)सार्वजनिक और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में स्थापित अस्पतालों की संख्या 2694 (1951) से बढ़कर 13692 (1993), औषधालयों की संख्या 5306 (1951) से बढ़कर 28321 (1993) और पलंगा की संख्या 117179 (1951) से बढ़कर 843650 (1993) हो गई हैं। यह वृद्धि जनसंख्या में हुई वृद्धि की रफ्तार के अनुसार नहीं हुई हैं जिस से सरकारी अस्पतालों जो समाज के निम्न कम दौलतमंद वर्गो की जरूरतों की पूरा करते हैं, में अत्यधिक भीड़ हो गई हैं।

"स्वास्थ्य" राज्य का एक विषय हैं और राज्यों में लोगों की महसूस की गई जरूरतों को देखते हुए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना और स्वास्थ्य क्षेत्र में पर्याप्त निवेश करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी हैं।

सरकारी अस्पतालों में अत्यधिक भीड़ रेफरल पद्धतियों के अभाव के कारण भी हैं जहां रोगियों की जांच प्राथमिक केन्द्रों, उप जिला और जिला स्तर के अस्पतालों में की जा सकती हैं । प्रमुख सरकारी अस्पतालों पर दबाव को कम करने के लिए आन्ध्र प्रदेश (परियोजना परिव्यय 608.00 करोड़ रुपये), कर्नाटक (परियोजना परिव्यय - 546.00 करोड़ रुपये), पंजाब, (परियोजना परिव्यय - 425.00 करोड़ रुपये), पश्चिम बंगाल, (परियोजना परिव्यय- 689.00 करोड़ रुपये), उड़ीसा (परियोजना परिव्यय - 415.57 करोड़ रुपये) और महाराष्ट्र (परियोजना परिव्यय - 158.1 मिलियन अमरीकी डालर) द्वारा विश्व बैंक सहायता से उप जिला स्तर के अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि रोगियों की उपयुक्त जांच हो और सरकारी अस्पतालों में अत्यधिक भीड़ न होने देने के लिए स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे के विभिन्न स्तरों पर सुविधाएं प्रदान की जाएं, इस परियोजना के बाद के चरणों मेंऔर अधिक राज्यों को कवर करने का विचार हैं।

केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों के लिए 1999-2000 के लिए योजना आवंटन इस प्रकार हैं :-

सफदरजंग अस्पताल25.93 करोड़ रुपये

डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल 12.57 करोड़ रुपये लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज 8.45 करोड़ रुपये

कलावती सरन ताल अस्पताल .82 करोड़ रुपये

जवाहरलाल आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान

संस्थान पांडिचेरी 13.50 करोड़ रुपये

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान 81.00 करोड़ रुपये

स्नोतकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान

संस्थान, चंडीगढ़ 47.00 करोड़ रुपये

विभिन्न केन्दीय अस्पतालों में हाल में निम्नलिखित सुविधाएं विकसित की गई हैं :-

(i) केन्द्रीय विकलांग संस्थान, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में एक आथोरसकोपीं और स्पोर्ट्स इन्जरी क्लिनिक की स्थापना की गई हैं।

(ii) सफदरजंग अस्पताल के हृद-वक्ष वाहिका शल्य चिकित्सा विभाग और हृद विज्ञान विभाग को 529 करोड़